बनवारी लाल

बनाम

त्रिलोक चाँद और अन्य

(और इसके विपरीत शीर्षक)

23 अक्टूबर, 1979

[एन.एल. अंतवालिया और ए.डी. कौशल, जे.जे.]

हिंदू कानून - गोद लेना - वसीयत में यह कथन कि अमुक व्यक्ति दत्तक पुत्र है, यदि गोद लेने का पर्याप्त प्रमाण हो - गोद लेने के परीक्षण - क्या हैं।

एम के पुत्र एस के जी और जे पुत्र थे। वादी एम के दुसरे पुत्र का पोता था। जी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले एक दस्तावेज़ में कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 उसका (जी का) दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था और वह सी (उसके छोटे भाई जे की विधवा) और प्रतिवादी संख्या 1 ने उनकी सेवा की थीं, जिसकी मान्यता के लिए उसने वसीयत में विस्तृत संपत्तियों को सी को विरासत में दिया उसके जीवन काल के दौरान उसके द्वारा आनंद लिया गया और उसकी मृत्यु पर प्रतिवादी नंबर 1 उनका मालिक होगा।

वादी ने विभाजन के लिए अपने मुकदमे में दावा किया कि वादी की अनुसूची ए में वर्णित संपत्तियां उसके परदादा एम द्वारा अर्जित की गई थीं, अनुसूची बी में संपत्तियां जी और जे द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित की गई थीं, जो दोनों एक संयुक्त हिंदू परिवार का गठन करते थे, और वे अनुसूची सी में जो एक बार विशेष रूप से जे का था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा सी के पास आ गया। वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 की गोद लेने को भी चुनौती दी।

दूसरे पक्ष के प्रतिवादी नंबर 1 ने दावा किया कि चूंकि वह जी का दत्तक पुत्र था, इसलिए जी की वसीयत से उसे जो संपत्ति मिली थी, वह उसकी विशेष संपत्ति थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अनुसूची सी में संपत्तियां जे की विधवा सी ने अपनी पत्नी से खरीदी थीं, उसकी वसीयत के कारण वह विशेष रूप से उन संपत्तियों का हकदार था और वे कभी भी उसके दिवंगत पति की नहीं थीं।

विचारण न्यायालय ने माना कि गोद लेने को साबित नहीं किया गया था और वसीयत के निष्पादन का मकसद केवल वसीयतकर्ता द्वारा गोद लेने वाले के साथ अपने रिश्ते की मान्यता नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से उसके लिए प्यार और स्नेह की भावनाओं का अस्तित्व था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना कि जी की वसीयत में यह कथन कि प्रतिवादी नंबर 1 उसका दत्तक पुत्र था, गोद लेने के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त था।

दूसरी ओर, उच्च न्यायालय की राय थी कि जी की वसीयत में यह कथन कि प्रतिवादी नंबर 1 उसका दत्तक पुत्र था, गोद लिए गए को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था और गोद लेने का संदर्भ केवल वसीयत के विवरण के रूप में किया गया था, न कि वसीयत के निष्पादन के लिए प्रेरणा के रूप में।

अभिनिर्धारित: प्रतिवादी संख्या 1 कथित गोद लेने को स्थापित करने में सफल नहीं हुआ था। [1005 एफ]

1. (ए) यह अच्छी तरह से स्थापित है कि गोद लेने के समर्थन में साक्ष्य उस गंभीर और गंभीर दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति पर होता है जो गोद लेने का आरोप लगाकर प्राकृतिक उत्तराधिकार को विस्थापित करना चाहता है। [1005 डी-ई]

(बी) इस मामले में गोद लेने के सबूत का बोझ प्रतिवादी नंबर 1 पर भारी पड़ा, जिसे उसने संतोषजनक ढंग से निर्वहन नहीं किया है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुकदमा दायर किए जाने के काफी समय बाद गोद लिया गया हो। वास्तव में यह मुक़दमे से तुरंत पहले लगभग एक दशक के भीतर हुआ था जब गवाह जो समारोह में उपस्थित थे और जिन्होंने लेन-देन होते देखा था, सामान्यतः उपलब्ध होते थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि ऐसा कोई गवाह क्यों नहीं आया। [1005 ए-बी]

(सी) वसीयत में उल्लिखित संबंध कि प्रतिवादी नंबर 1 उसका दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी था, वसीयतकर्ता द्वारा समझे गए वसीयतकर्ता का केवल एक विवरण था। वसीयत निष्पादित नहीं की गई थी क्योंकि वह रिश्ता गोद लेने के कारण बना था, बल्कि स्नेह की भावनाओं के कारण था, जो कि वसीयतकर्ता ने उसके सहयोग से और वसीयतकर्ता को प्रदान की गई सहायता से अर्जित की थी। [1003 एच-1004 ए]

2. वादी के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि जहां तक अनुसूची ए और बी में विस्तृत संपत्तियों का संबंध है, सी द्वारा निष्पादित वसीयत को पूरी तरह से निष्क्रिय माना जाना चाहिए क्योंकि इन अनुसूचियों में उल्लिखित संपत्तियों का आधा हिस्सा जी की वसीयत के तहत सी में निहित था, जिसने स्वयं घोषणा की थी कि वह उन्हें केवल एक आजीवन किरायेदार के रूप में रखेगी और उसके बाद वे प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तांतरित कर देंगे। प्रतिवादी नंबर 1 के लिए संपत्तियों को तैयार करने में, सी ने अपने स्वयं के न्यायाधीश के इशारे को पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं किया, जो कि कानूनी रूप से सही था। [1004 ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1742-1743/1969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आर.एस.ए. सं. 2777/1972 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 12-12-1968 से।

सीए 1742/69 में अपीलार्थी की ओर से एस. एन. एंडले, उमा दत्ता और टी. सी. शर्मा।

सीए 1742/69 में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ए. पी. एस. चौहान और एन. एन. शर्मा और सीए 1742/69 में अपीलार्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया-

कौशल, न्यायाधिपति. - विशेष अनुमति द्वारा इन दो क्रॉस अपीलों को जन्म देने वाले तथ्य, लाभ के साथ, निम्नलिखित वंशावली तालिका के संदर्भ में बताए जा सकते हैं-

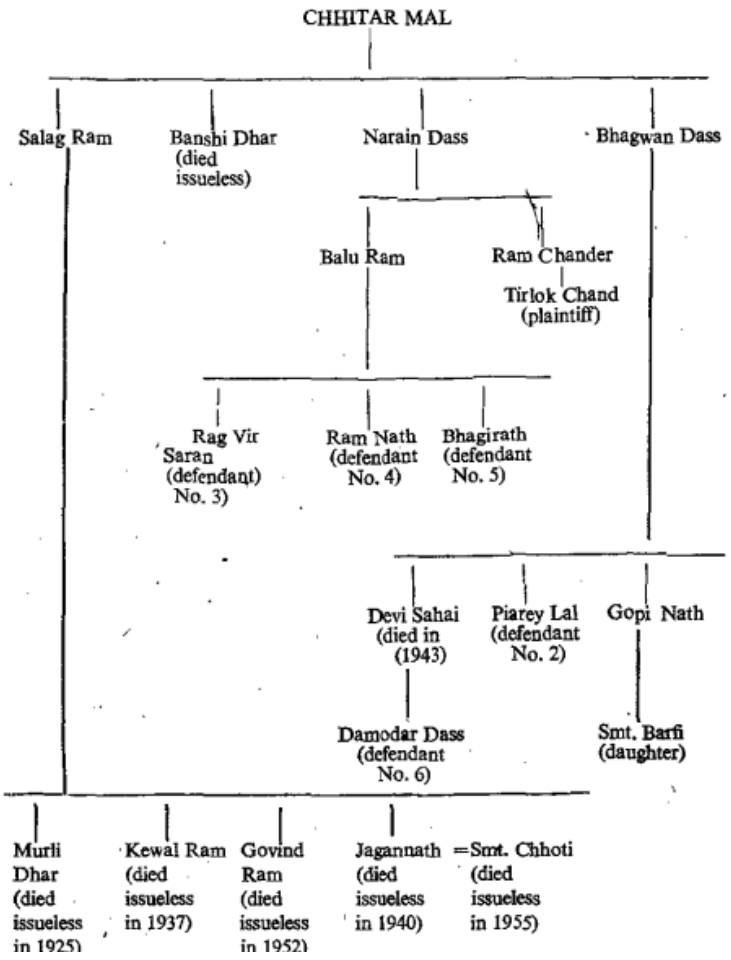

पक्ष और सी में वर्णित सं हुआ। उनका मामला य ा छीतर मल द्वारा अर्जि राम के बेटों जगन्नाथ थी, जिनमें से दोनों एक निर्दिष्ट संपत्ति एक बार ि ौर यह उनसे थी कि यह प्रति ी-तालिका में दिखाई देते हैं, बनवारी लाल [जो सिविल अपील संख्या 1742 (एन)/1969 में

हमारे सामने अपीलकर्ता हैं] को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में रखा गया था और वह रहे हैं। वास्तविक प्रतिस्पर्धी प्रतिवादी जिसका दावा छीतर मल के पोते गोविंद राम द्वारा गोद लिए जाने और दो पंजीकृत वसीयतों पर आधारित था, दोनों की तारीख 25 सितंबर, 1950 थी। करने के लिए अभिप्राय क्रमशः गोविंद राम और श्रीमती छोटी द्वारा निष्पादित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि दोनों वसीयतकर्ताओं ने अपनी पूरी संपत्ति उन्हें दे दी थी, अनुसूची ए के अंतर्गत आने वाली संपत्ति छितर मल द्वारा नहीं बल्कि सालग राम द्वारा अर्जित की गई थी और अनुसूची सी में शामिल संपत्ति को श्रीमती छोटी ने अपने स्त्रीधन से खरीदा था और था कभी भी अपने पति जगन्नाथ की संपत्ति नहीं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अपने लिए मुकदमे में सभी संपत्तियों के हकदार होने का दावा किया, यह पार्टियों के बीच सामान्य आधार था कि वे संपत्तियां दो वसीयतों की विषय-वस्तु थीं।

वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा स्थापित गोद लेने से इनकार कर दिया और दो वसीयतों को जालसाजी के रूप में चुनौती दी।

विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पाया कि अनुसूची ए के अंतर्गत आने वाली संपत्ति छितर मल द्वारा नहीं बल्कि उनके बेटे सालग राम द्वारा अर्जित की गई थी। अनुसूची बी द्वारा ग्रहण की गई संपत्ति के संबंध में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इसलिए इसे गोविंद राम और जगन्नाथ द्वारा उनकी संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति के हिस्से के रूप में

संयुक्त रूप से अर्जित किया गया माना गया था। अनुसूची सी में वर्णित संपत्ति के संबंध में, विचारण न्यायालय ने माना कि इसे जगन्नाथ द्वारा अधिग्रहित किया गया था, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निष्कर्ष को उलट दिया, जिसमें पाया गया कि अधिग्रहण श्रीमती छोटी द्वारा अपने स्वयं के धन से किया गया था, उनके पति जगन्नाथ को इसमें कोई रुचि नहीं है।

प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से यह साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि उसे गोद दिया गया था या लिया गया था। इसलिए विचारण न्यायालय ने माना कि गोद लेना साबित नहीं हुआ था। हालाँकि, गोविंद राम की वसीयत में, यह लिखा था कि प्रतिवादी नंबर 1 उसका दत्तक पुत्र था और इस बयान को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गोद लेने को साबित करने के लिए पर्याप्त माना था। दोनों वसीयतों को वास्तविक और कानूनी रूप से वैध माना गया और इसलिए मुकदमा विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पूरी तरह से खारिज कर दिया गया।

द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ने गोद लेने से संबंधित मामले को छोड़कर प्रथम अपीलीय न्यायालय के सभी तथ्यों के निष्कर्षों को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय की राय थी कि गोविंद राम की वसीयत में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उसके द्वारा गोद लिए जाने के बारे में किया गया कथन गोद लेने को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसे इसलिए स्थापित नहीं

किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा आगे यह माना गया कि अनुसूची ए और बी में निर्दिष्ट संपत्ति में आधा हिस्सा केवल जीवन-किरायेदार के रूप में जगन्नाथ से श्रीमती छोटी को मिला है, वह इसे दूर करने में सक्षम नहीं थी और वादी, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह आधे हिस्से का उत्तराधिकारी होने का हकदार था।

उच्च न्यायालय के समक्ष जोरदार ढंग से यह तर्क दिया गया कि भले ही वसीयत को वास्तविक माना जाए, वे तभी काम करेंगे जब प्रतिवादी नंबर 1 को गोविंद राम द्वारा वैध रूप से गोद लिया हुआ दिखाया गया था क्योंकि गोविंद राम और श्रीमती छोटी दोनों ने उसे गोविंद राम का दत्तक पुत्र बताया था और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उसने गोविंद राम का दत्तक पुत्र होने के कारण प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की है। इस विवाद को उच्च न्यायालय ने (जैसा कि विचारण न्यायालय ने भी किया था) इस आधार पर खारिज कर दिया था कि दोनों वसीयतों में से प्रत्येक में गोविंद राम के दत्तक पुत्र के रूप में प्रतिवादी नंबर 1 का उल्लेख केवल एक विवरण के रूप में किया गया था। वसीयत करने वाले की और किसी भी वसीयत के निष्पादन के लिए प्रेरणा के रूप में नहीं। इस दृष्टिकोण के लिए रंगनाथन चटियार और अन्य बनाम पेरिस्करुप्पन और अन्य [(1)] से समर्थन लिया।

परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने वादी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, मुकदमे की बर्खास्तगी को रद्द करें और उसके (उच्च

न्यायालय के) फैसले के आलोक में, अपने पति से श्रीमती छोटी को मिली संपत्ति में पक्षकारों के शेयरों की घोषणा करने और उसके बाद तदनुसार संपत्ति के विभाजन के लिए मामले को विचारण न्यायालय में भेज दिया।

2. दोनों प्रतिस्पर्धी पक्ष उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित महसूस करते हैं। जबकि प्रतिवादी नंबर 1 सिविल अपील संख्या 1742/1969 में अनुसूची ए, बी और सी के अंतर्गत आने वाली पूरी संपत्ति का दावा करता है, वादी ने प्रतिवादी नंबर 1 के दावे को पूरी तरह से पराजित करने के लिए एक क्रॉस अपील (सिविल अपील संख्या 1743/1969) दायर की है।

3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। जहां तक तथ्य के निष्कर्षों का सवाल है, वे हमारे सामने चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हैं। पहला प्रश्न जो वादी पक्ष के विद्वान वकील ने हमारे सामने पुनः खोला है वह है क्या इस तथ्य के बावजूद कि दोनों वसीयतें प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में क्रियान्वित थीं, यह सही था कि उसने दत्तक पुत्र के रूप में अपना चरित्र स्थापित नहीं किया था, जैसा कि दोनों वसीयतों में उसे दिया गया विवरण था। इस सवाल पर भी हमें लगता है कि उच्च न्यायालय ने सही जवाब दिया है। इस संबंध में गोविंद राम की वसीयत के संबंधित भाग का संदर्भ लिया जा सकता है और उसे नीचे दिया गया है:

"श्री बनवारीलाल निष्पादक के दत्तक पुत्र और उत्तराधिकारी हैं। श्रीमती छोटी पिलखुवा, परगमत डासना, तहसील

गाजियाबाद के निवासी जगन्नाथ प्रसाद की विधवा हैं। दोनों व्यक्ति निष्पादक के साथ रहते हैं और निष्पादक को सभी उचित सेवाएँ प्रदान करते हैं। इसलिए, मैं निम्नलिखित वसीयत करता हूं: कि निष्पादक की मृत्यु के बाद मेरी सभी संपत्ति, चल और अचल, अन्य सभी सामान और घरेलू संपत्ति के साथ-साथ धर्मशाला नंबर 1I60 और नीचे दी गई एक मंजिला दुकान नंबर 1/57 का स्वामित्व श्रीमती छोटी विधवा के पास होगा। -जगन्नाथ प्रसाद, व्यवसायिक दुकानदार, निवासी पिलखुवा, जिन्हें संपत्ति बेचने का कोई अधिकार नहीं होगा। उसे धर्मशाला से जुड़ी दुकान नंबर 1/57 की आय को धर्मशाला के लिए खर्च करने का अधिकार होगा। श्रीमती की क्लीथ के बाद. छोटे, बनवारीलाल, दत्तक पुत्र और निष्पादक का उत्तराधिकारी, मालिक होगा....."

इस दस्तावेज़ की व्याख्या करने और मामले की आसपास की परिस्थितियों पर विचार करने पर, विचारण न्यायालय ने पाया कि वसीयत के निष्पादन का मकसद वसीयतकर्ता द्वारा वसीयतकर्ता के साथ गोद लेने के माध्यम से अपने रिश्ते की मान्यता मात्र नहीं था, बल्कि मुख्य रूप से प्रेम की भावनाओं का अस्तित्व था। उसके प्रति स्नेह. यह एक तथ्य के रूप में पाया गया कि बनवारी लाल गोविंद राम और श्रीमती छोटी के साथ रह रहे थे, कि उन्होंने उनकी बीमारी के दौरान उनकी सेवा की थी और वह

उनसे स्नेहपूर्वक जुड़े हुए थे, इसलिए जब वसीयत निष्पादित की गई तो उनके करीब कोई नहीं था। या गोविंद राम और श्रीमती छोटी को बनवारी लाल से अधिक प्रिय। मामले के इस दृष्टिकोण में, कथित संबंध स्थापित करने में विफलता विचाराधीन बिंदु के लिए निर्णायक नहीं है, और जैसा कि उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, ऐसा प्रतीत होता है कि वसीयतकर्ता ने उस कारण से वसीयत नहीं की है जो उसने वास्तव में और कानूनी रूप से की थी। उन्होंने बनवारी लाल को गोद लिया, लेकिन इस कारण से कि उन्होंने बनवारी लाल को एक दत्तक पुत्र के रूप में माना और जो सेवा उन्होंने उन्हें प्रदान की, उससे वे वास्तव में प्रभावित हुए। वसीयत में उल्लिखित संबंध केवल वसीयतकर्ता का एक विवरण था, जैसा कि वसीयतकर्ता द्वारा समझा गया था जिसने वसीयत को वसीयतकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया था, न कि गोद लेने के कारण पैदा हुए रिश्ते के कारण। बल्कि स्नेह की भावनाओं के कारण जो वसीयतकर्ता ने उसके सहयोग और सहायता से अर्जित की थी।

4. वादी की ओर से उठाया गया एकमात्र अन्य उल्लेखनीय मुद्दा यह था कि जहां तक अनुसूची ए और बी में बंद संपत्तियों का संबंध है, श्रीमती छोटी द्वारा निष्पादित वसीयत को पूरी तरह से निष्क्रिय माना जाना चाहिए। उस विवाद में भी कोई बल नहीं है। उन दो अनुसूचियों में उल्लिखित संपत्तियों का आधा हिस्सा गोविंद राम की वसीयत के तहत श्रीमती छोटी को सौंप दिया गया था, जिसमें स्वयं घोषित किया गया था

कि श्रीमती छोटी उन्हें केवल जीवन-किरायेदार के रूप में रखेंगी और इसके बाद वे प्रतिवादी नंबर 1 पर स्थानांतरित हो जाएंगे। उन संपत्तियों को प्रतिवादी नंबर 1 के नाम करने में श्रीमती छोटी ने अपने वसीयतकर्ता के आदेश को पूरा करने के अलावा और कुछ नहीं किया, जो आदेश कानून की दृष्टि से अच्छा था और प्रभावी होता। भले ही श्रीमती छोटी ने गोविंद राम की वसीयत के तहत अर्जित संपत्तियों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की थी।

5. प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से एकमात्र निवेदन यह था कि दोनों वसीयतों को न केवल श्रीमती छोटी द्वारा गोविंद राम से प्राप्त संपत्तियों के संबंध में, बल्कि उन संपत्तियों के संबंध में भी प्रभावी किया जाना चाहिए, जो उन्हें संपत्ति अपने पति जगन्नाथ की उत्तराधिकारी के रूप में सौंपी गई थीं। यह निवेदन भी तथ्यहीन है। 1940 में जगन्नाथ की मृत्यु हो गई जब श्रीमती छोटी सामान्य जीवन-अवधि पर बिना किसी अलगाव (आवश्यकता को छोड़कर) या वसीयत के अधिकार के उनकी संपत्ति में आ गईं। इस हद तक कि उसने जगन्नाथ की संपत्ति को तैयार करने में अपने अधिकारों का उल्लंघन किया, वसीयत ने कानून का उल्लंघन किया और उचित रूप से निष्क्रिय माना गया, इसका परिणाम यह हुआ कि अनुसूची ए और बी के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों में उसके वसीयतकर्ता, न कि उसके वसीयतकर्ता, जगन्नाथ की हिस्सेदारी पाने में सफल होंगे। यदि गोद लेने की बात साबित हो जाती तो स्थिति निश्चित रूप से अलग होती, उस

स्थिति में, प्रतिवादी नंबर 1 श्रीमती छोटी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के एकमात्र प्रतिशोधकर्ता के रूप में सफल होता, क्योंकि वह उनके पति के भाई का बेटा है और इसलिए उनका सबसे करीबी और एकमात्र वारिस है और यही कारण है कि प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से एक विवाद उठाया गया था कि एक वैध गोद लेने को साबित कर दिया गया था और नीचे की दो अदालतों द्वारा इसके विपरीत जो निष्कर्ष निकाला गया था वह समर्थन योग्य नहीं था। इस संबंध में गोविंद राम द्वारा निष्पादित वसीयत में प्रतिवादी नंबर 1 के विवेचक का दत्तक पुत्र होने का उल्लेख किया गया था। और राज पाल, डीडब्ल्यू-2 के मौखिक साक्ष्य के लिए, जिन्होंने उस वसीयत को प्रमाणित किया और बताया कि प्रतिवादी नंबर 1 को वसीयतकर्ता द्वारा अपनाया गया था। साक्ष्य के इन दो टुकड़ों पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया, दोनों ने सामग्री को यह मानने के लिए अपर्याप्त माना कि वैध गोद लेने को साबित किया गया था। गोद लेने के संबंध में निष्कर्ष तथ्य का निष्कर्ष है जिसे हम देखते हैं मामले की परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि गोद लेने की प्रक्रिया पक्षों के बीच मुकदमे से ठीक पहले लगभग एक दशक के भीतर हुई थी, ताकि गवाहों के साक्ष्य जो वास्तविक गोद लेने के समय मौजूद थे और जिन्होंने गोद लेने को देखा था। 'देना और लेना' सामान्यतः उपलब्ध होता। हालाँकि, ऐसा कोई गवाह पेश करने का कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही यह बताने का प्रयास किया

गया कि ऐसा कोई गवाह क्यों नहीं आया। यदि गोद लेने के प्रमाण को बहुत लंबी अवधि के बाद न्यायालय में प्रस्तुत करना आवश्यक होता, तो अलग-अलग विचार प्रबल हो सकते थे, जो यहां मामला नहीं है। गोद लेने के बारे में वसीयतकर्ता द्वारा दिया गया बयान निश्चित रूप से स्वीकार्य साक्ष्य का एक टुकड़ा है, जैसा कि चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह बनाम बिशेश्वर प्रताप नारायण सिंह [(1)] मामले में प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है। लेकिन इस सिद्धांत को निर्धारित करने वाला कोई कानून या विवेक नहीं है कि इस तरह के बयान को निर्णायक माना जाना चाहिए, और उस मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था। और गोद लेने के सबूत का बोझ प्रतिवादी पर भारी था। इस संबंध में हम मुल्ला के हिंदू कानून (14वें संस्करण) के अनुच्छेद 512 में निम्नलिखित अंश का उल्लेख कर सकते हैं:

> " ..... लेकिन गोद लेने के समर्थन में सबूत उस गंभीर और गंभीर जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति पर है जो प्राकृतिक को विस्थापित करना चाहता है। गोद लेने का आरोप लगाकर उत्तराधिकार। यह जिम्मेदारी विशेष रूप से भारी होती है जहां गोद लेने के कथित प्राधिकारी की तारीख के काफी समय बाद गोद लिया जाता है..."

यह सच है, जैसा कि मुल्ला ने उसी लेख के एक बाद के अंश में बताया है कि जब गोद लेने और उस पर सवाल उठाए जाने के बीच बहुत लंबी अवधि का अंतराल होता है, तो गोद लेने के तथ्य को साबित करने के लिए सबूतों की अनुपस्थिति को हर तरह से नजरअंदाज किया जाता है। अनुकूल मनोरंजन किया जाना चाहिए; लेकिन यहाँ वैसी स्थिति नहीं है जैसी हम पहले ही बता चुके हैं। इसलिए हम उच्च न्यायालय के इस मत के साथ हैं कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, प्रतिवादी नंबर 1 कथित गोद लेने की स्थापना में सफल नहीं हुआ है।

6. परिणामस्वरूप दोनों अपीलें विफल हो जाती हैं और लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती हैं।

पीबीआर.

अपीलें खारिज की गई।

(1) ए.आई.आर. 1957 एस सी 815.

(1) ए.आई.आर. 1927 पटना 61.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक श्री विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****